

भोपाल	21.0°	37.0°
इंदौर	20.0°	38.0°
जबलपुर	27.0°	39.0°
ग्वालियर	28.0°	41.0°
सागर	25.0°	39.0°

**राजधानी... एक पेड़ माँ के नाम: मुख्यमंत्री ने किया पौधरोपण...**

**खेल... लार्ड्स टेस्ट: अब मूविंग डे तीसरे नहीं पहले दिन होता है...**

**व्यापार... सर्राफा बाजार में सोने के भाव में मामूली ...**

**देश-विदेश... बांग्लादेश में अवामी लीग की नेता ...**

## आरएसएस के विरुद्ध टिप्पणी करने पर कांग्रेस आईटी सेल जिला अध्यक्ष गिरफ्तार फेसबुक पोस्ट से विवाद, सारंगपुर में तनाव के बाद पुलिस ने की कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में डिगवाड़ निवासी कांग्रेस नेता एवं आईटी सेल जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह चंदेल को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया है।



जिससे सामाजिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। मामला सामने आने के बाद हिंदू समाज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं ने सारंगपुर थाने पहुंचकर विरोध जताया और ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से सामाजिक सौहार्द प्रभावित होता है और इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि किसी भी संगठन या समुदाय के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग स्वीकार्य नहीं है और ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया पोस्ट की विस्तृत जांच की जा रही है और उसके आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। इस घटना के बाद क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक हलचल देखी गई। बड़ों संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग भी थाने पहुंचे थे।

पुलिस के अनुसार चंदेल ने फेसबुक पर एक पोस्ट साझा की थी, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की गई थी। आरोप है कि इस पोस्ट में संगठन को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया गया, जिससे सामाजिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया पोस्ट की विस्तृत जांच की जा रही है और उसके आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। इस घटना के बाद क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक हलचल देखी गई। बड़ों संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग भी थाने पहुंचे थे।

## अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर वार्ता जारी, अतिरिक्त आयात शुल्क के प्रस्ताव से बढ़ी चिंता ट्रंप बोले - मोदी से अच्छे संबंध, डील संभव

वाशिंगटन डी.सी., एजेंसी: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को लेकर बयान देते हुए कहा कि भारत ने दशकों तक अमेरिका के साथ ऊँचे आयात शुल्क लगाकर लाभ उठाया है। उन्होंने दावा किया कि अब स्थिति बदल चुकी है और अमेरिका भारत से अच्छी आय अर्जित कर रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भारत के साथ जल्द ही एक बड़ा व्यापार समझौता संभव है, क्योंकि उनके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे संबंध हैं। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी उनके अच्छे मित्र हैं और दोनों देशों के बीच आपसी समझ और सहयोग का माहौल है। उन्होंने संकेत दिया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है और दोनों पक्ष इसे जल्द अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक दिशा में चल रही है और ऐसा समझौता तैयार किया जा रहा है जिससे दोनों देशों को लाभ हो सके। हाल ही में दोनों देशों के



अधिकारियों के बीच कई दौर की वार्ता भी हुई है, जिसका उद्देश्य लंबित व्यापारिक मुद्दों का समाधान करना है। उधर अमेरिका ने कुछ देशों पर अतिरिक्त आयात

प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है। इससे भारतीय निर्यात मंहगा हो सकता है और व्यापार पर प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रस्ताव अभी अंतिम निर्णय नहीं है और इस पर विभिन्न पक्षों की राय ली जाएगी, जिसके बाद ही कोई अंतिम फैसला किया जाएगा। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते का प्रारूप पहले ही तैयार किया जा चुका है, लेकिन कुछ कानूनी और नैतिक कारणों से इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है।

## प्रधानमंत्री ने 18,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया

**पीएम मोदी बोले - आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर दिया गया जोर**

## दूसरों पर निर्भर देश कभी विकसित नहीं बन सकते

नईदुनिया ब्यूरो, सूरत: पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस कांग्रेस 12 सालों से अराजकता और अनिश्चितता फैला रही है। कर्नाटक की जनता भी कांग्रेस की नकारात्मकता के नाराज है। इसलिए कर्नाटक में सीएम बदलना पड़ा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले देश विकसित नहीं होते हैं। आज देश में कुछ निराशावादी लोग हैं। जिन्होंने देश को दूसरों पर निर्भर रखा, आज वो आत्मनिर्भर भारत का मजाक उड़ा रहे हैं। पीएम ने गुजरात के सूरत में ये बातें कही। उन्होंने वहां से 18 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो देश दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वे कभी भी विकसित नहीं बन सकते। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत



की अवधारणा पर जोर देते हुए कहा कि कुछ लोग निराशावादी सोच के कारण इस अभियान का मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि भारत आज 140 करोड़ नागरिकों के

सहयोग से वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में दुनिया ने पहले महामारी और उसके बाद तेल, पेट्रोल तथा गैस की आपूर्ति में गंभीर संकट का सामना किया

है, लेकिन भारत ने अपनी क्षमता और आत्मनिर्भरता के बल पर इन परिस्थितियों का सामना किया है। उन्होंने सूरत को स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार पुरस्कार प्राप्त करने वाला शहर बताते हुए कहा कि सूरत केवल एक शहर नहीं, बल्कि एक सोच और ऊर्जा का प्रतीक है।

इससे पहले पीएम प्रधानमंत्री ने सूरत में लार्सन एंड टुब्रो के आईटी सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स भी पहुंचे। उन्होंने यहां मेड इन इंडिया टैंक, ड्रोन के सामने खड़े होकर उसकी जानकारी ली।

एल एंड टी कॉलेक्स भारत का अत्याधुनिक रक्षा निर्माण केंद्र है। यहां सेना के लिए बखरबंद वाहन, तोप से जुड़े सिस्टम और अन्य सैन्य प्लेटफॉर्म बनाए, असेंबल (जोड़े) और परीक्षण

किए जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आगंतुकों को साइकिल तथा विद्युत वाहन से आने के लिए प्रोत्साहित किया गया। नगर निगम द्वारा आम नागरिकों के लिए बड़ी संख्या में विद्युत बसों की व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री ने सड़क, बिजली और औद्योगिक विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया तथा कई योजनाओं की आधारशिला रखी।

इसके साथ ही उन्होंने वर्युअल माध्यम से दमन और लक्षद्वीप में बंदरगाह एवं पर्यटन परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री के इस दौरे को गुजरात के विकास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

## पर्यावरण संरक्षण हमारी सनातन जीवन पद्धति का हिस्सा: डॉ. यादव मुख्यमंत्री ने किया 'एक पेड़ माँ के नाम 2.0' अभियान का शुभारंभ

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण हमारी सनातन जीवन पद्धति का अभिन्न हिस्सा है और भारतीय संस्कृति में प्रकृति के सभी तत्वों को समान महत्व दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी परंपराओं, पूजा पद्धति और जीवन शैली में पर्यावरण संरक्षण की मूल भावना निहित है। उन्होंने यह विचार विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 'एक पेड़ माँ के नाम 2.0' अभियान के राज्य स्तरीय शुभारंभ समारोह में व्यक्त किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि जल रंगा संवर्धन अभियान के तहत नदियों, कुओं, बावड़ियों और तालाबों के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ



किया तथा परिसर में स्वर्ण चंपा, सीता अशोक, रामफल और आंवला के पौधे रोपे। उन्होंने आठ श्रेणियों में ग्यारह राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार भी प्रदान किए, जो औद्योगिक इकाइयों, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों और व्यक्तियों को दिए गए। कार्यक्रम में सर्वोत्तर अर्थव्यवस्था से संबंधित पाठ्यक्रम मॉड्यूल और जल संरक्षण से जुड़े प्रलेखन दस्तावेजों का विमोचन किया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और सतत विकास पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सुशासन और विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है तथा देश ऊर्जा संकट से उबर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य हरित ऊर्जा परियोजनाओं पर कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने भोपाल गैस त्रासदी का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण और सुरक्षा के प्रति गंभीर है तथा यूनिवर्सल कार्बाइड के अपशिष्ट का सफल निष्पादन किया गया है।

## 8 आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा के 66 अधिकारियों के तबादले

विधायक लोधी से विवाद पर चर्चा में रहे आयुष जाखड़ एसपी बने

जबलपुर में पति-पत्नी दोनों एसपी



सरकार ने उनकी पत्नी और भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी अनु बेनियाल का भी तबादला ग्वालियर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जबलपुर के पद पर किया है। दोनों अधिकारी अब जबलपुर में एक साथ सेवाएं देंगे। अनु बेनियाल भी पूर्व में एक विवादित मामले के कारण चर्चा में रही थी।

अधिकारी मिनी शुक्ला को पदोन्नति देकर भोपाल नगरीय पुलिस में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, जून-2 बनाया गया है। नई पदस्थापना के बाद वे भोपाल में सेवाएं देंगे। ओमप्रकाश को इंदौर नगरीय पुलिस, करणदीप को उज्जैन, गौरव पांडेय को सतना, राज कृष्णा को महु तथा सुजावल जग्गा को ग्वालियर में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

राज्य पुलिस सेवा के 66 अधिकारियों को भी विभिन्न जिलों, पुलिस इकाइयों तथा विशेष शाखाओं में नई पदस्थापना दी गई है। इनके नाम व पदस्थापना इस प्रकार है:

1. सीताराम सखवा
2. मुकेश कुमार वैश्य
3. आरडी प्रजापति
4. रेखा धर्मदत्त सिंह
5. अमित वर्मा
6. प्रवीं द्विवेदी
7. सुरेंद्र सिंह गौर

(शेष पेज 12 पर)

## ट्रंप बोले- ईरान के सर्वोच्च नेता से मिलने की इच्छा

तेल अवीव, तेहरान, वाशिंगटन डी.सी., एजेंसी: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यदि ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता होता है, तो वह ईरान के सर्वोच्च नेता मुजतबा खामेनेई से मिलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में यह मुलाकात संभव है और उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ट्रंप ने कहा कि संभावित मुलाकात सम्मानजनक होगी और वह ईरानी नेतृत्व के साथ सम्मान से पेश आएंगे। अमेरिका ने पहले ईरान से संबंधित यूरेनियम प्राप्त करने के लिए सैन्य कार्रवाई पर विचार किया था, लेकिन अत्याधिक जोखिम के कारण यह योजना रोक दी गई। उन्होंने कहा कि सैनिकों की सुरक्षा को देखते हुए इस कदम को आगे नहीं बढ़ाया गया।

## बिना प्रक्रिया किसी को सीमा पार नहीं भेज रहे, भारत का बांग्लादेश को जवाब

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भारत ने बांग्लादेश को उस आरोप पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें कहा गया था कि पिछले चौबीस घंटों में भारत ने कुछ लोगों को जबरन सीमा पार भेजने की कोशिश की, जिसे बांग्लादेशी अधिकारियों ने रोक दिया। भारत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना निर्धारित प्रक्रिया पूरी किए सीमा पार नहीं भेजा जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों से निपटने के लिए स्पष्ट

कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को बांग्लादेश का नागरिक माना जाता है तो उसका मामला पहले बांग्लादेश सरकार को भेजा जाता है और नागरिकता की पुष्टि की जाती है। उन्होंने कहा कि केवल नागरिकता की पुष्टि होने के बाद ही निर्वासन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। ऐसे कई मामले बांग्लादेश के पास लंबित हैं और भारत उनके जवाब का इंतजार कर रहा है। उम्मीद जताई है कि इस प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा ताकि अवैध प्रवासियों के निपटान को कार्रवाई सुचारु रूप से आगे बढ़ सके।

## अन्नामलाई ने भाजपा छोड़ी, नई पार्टी बनाई

नईदुनिया ब्यूरो, चेन्नई: तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने पार्टी से अलग होकर नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि वह तमिलनाडु में एक नए राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी। अन्नामलाई ने कहा कि पिछले कई महीनों से उनके और पार्टी नेतृत्व के बीच मतभेद चल रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने चार दिसंबर 2025 को ही पार्टी से इस्तीफा देने की सूचना दे दी थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उन्हें चुनाव तक रुकने का आग्रह किया था।

## मनपसंद विभाग नहीं मिलने पर मंत्री रेड्डी का इस्तीफा

नईदुनिया ब्यूरो, बेंगलुरु: कर्नाटक में मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार की सरकार में मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने विभाग आवंटन से असंतुष्ट होकर इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बेंगलुरु विकास विभाग की जगह जल संसाधन विभाग की सेवाएं देना, जिससे वे नाराज बताए जा रहे हैं। रेड्डी ने कहा कि वे अब भी कांग्रेस में बने हुए हैं और केवल मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से वे पार्टी में विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं और कभी किसी पद की मांग नहीं की। मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने कहा कि यह कोई गंभीर मामला नहीं है।

रूस-भारत मिलकर बनाएंगे एसयू-57 विमान सेंट पीटर्सबर्ग, एजेंसी: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को सुखोई एसयू-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान को लेकर बड़ा प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि रूस भारत के साथ मिलकर इस पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का संयुक्त विकास और उत्पादन करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही रूस ने भारत को आवश्यक रक्षा तकनीक साझा करने की भी पेशकश की है। पुतिन ने कहा कि यह परियोजना पहले ही भारत को साझेदारी के लिए प्रस्तावित की गई थी, लेकिन उस समय भारत ने पहले रूस से प्रगति देखने के बाद शामिल होने की बात कही थी।

## रिपोर्ट युद्ध-टैरिफ संकट के बावजूद समग्र विकास दर मजबूत...

# देश की अर्थव्यवस्था 7.7% की दर से बढ़ी, अनुमान से बेहतर

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: युद्ध-टैरिफ संकट के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में अनुमान से बेहतर प्रदर्शन किया है। जारी आंकड़ों के अनुसार पूरे वर्ष की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत रही, जो सरकार के फरवरी में लगाए गए 7.6 प्रतिशत के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में यह दर 7.1 प्रतिशत थी। हालांकि, सरकार ने संकेत दिया है कि आगामी वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि की गति घटकर लगभग 6.6 प्रतिशत रह सकती है। वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी से मार्च तिमाही में देश की

अर्थव्यवस्था 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी। हालांकि, इस दौरान विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 12.8 प्रतिशत से घटकर 7.3 प्रतिशत पर आ गई, जिससे कुल आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार में हल्की गिरावट देखी गई। इसी कारण चौथी तिमाही की वृद्धि दर तीसरी तिमाही के 8 प्रतिशत के मुकाबले थोड़ी कम रही।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के प्रदर्शन को दर्शाने वाली सकल मूल्य वर्धन दर पूरे वित्त वर्ष में 7.9 प्रतिशत दर्ज की गई है। चौथी तिमाही में भी यह वृद्धि दर 7.9 प्रतिशत ही रही। भारतीय रिजर्व



बैंक के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में आर्थिक विकास दर लगभग 6.6 प्रतिशत रह सकती है, जो मौजूदा स्तर से थोड़ी कम होगी। इससे संकेत मिलता है कि

आने वाले समय में विकास की गति सामान्य हो सकती है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने इस बार जीडीपी आंकड़ों को नए आधार

वर्ष 2022-23 के अनुसार प्रस्तुत किया है। इससे पहले 2011-12 को आधार वर्ष माना जाता था। नए आधार वर्ष में अर्थव्यवस्था के स्वरूप में आए बदलावों को शामिल किया गया है, जिसमें डिजिटल सेवाएं, ई-कॉमर्स, सेवा क्षेत्र और अन्य नए आर्थिक घटक भी शामिल हैं। नई गणना प्रणाली में घरों में काम करने वाले श्रमिकों, वाहन सेवाओं तथा अन्य असंगठित क्षेत्रों के आंकड़ों को भी शामिल किया गया है, जिससे आर्थिक आकलन अधिक सटीक हो सके। सरकार ने स्पष्ट किया है कि समय-समय पर आधार वर्ष

बदलना अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होता है, ताकि अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति का बेहतर आकलन किया जा सके। सामान्यतः यह बदलाव हर पांच से दस वर्ष में किया जाता है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि नए आधार वर्ष के कारण आंकड़ों की गुणवत्ता और पारदर्शिता में सुधार होगा, जिससे नीति निर्माण और निवेश निर्णय अधिक प्रभावी बनेंगे। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि पुराने आंकड़ों को भी नए आधार वर्ष के अनुसार पुनः तैयार किया जाएगा, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक विश्लेषण संभव हो सकेगा।